इस युद्ध में रुकना एक अपराध होगा

अन्ना हजारे के आंदोलन की सफलता के रूप में हमारी लोकतांत्रिक परंपरा जीती। भ्रष्टाचार देश की मुख्य समस्याओं में से एक है। ऐसी समस्याएं, जिन्होंने तरक्की को कुंद करके रखा हुआ है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, काला धन, महंगा , अराजकता, नाइंसाफी, सामाजिक असमानता, राजनैतिक निरंकुशता, अपराध ऐसे ही बुनियादी मुद्दे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्ट न होने वाली तथा राह से न भटकने वाली एक लंबी मुहिम की इस देश का नागरिक कई दशकों से बाट जोह रहा है। अगर अन्ना हजारे की जगह को अन्य गैर-विवादीत, गैर-राजनैतिक और साफ-सुथरी छवि वाला व्यक्ति भी ऐसे बुनियादी मुद्दों पर लड़ाई छेड़ने की पहल करेगा तो लोग उसके पीछे उसी तरह आ खड़ें होंगे जैसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर पांच दिन तक चले कुछ सौ लोगों के आमरण अनशन का समर्थन करने के लिए उमड़ पड़े थे। इस देश को सच्चा के हक में खड़े होने वाले एक अदद नायक की तलाश है। लगता है कि सादा जीवन जीने वाले, निर्विवाद और नि:स्वार्थ, गैर राजनैतिक गांधीवादी अन्ना हजारे के रूप में हमें यह नायक मिल गया है। अन्ना जमीन के नेता हैं और इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उनके पांव जमीन पर ही टिके रहे, यह सिद्ध करता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नेता के रूप में वे कितने अनुकूल हैं। अन्ना को सफलता की खुशी के साथ-साथ उसके साथ आ चुनौती का पूरा अहसास है। नतीजे देने की चुनौती जो आने वाले दिनों में उनके सामने आ खड़ी होगी।

देश के हर दूसरे नागरिक को प्रभावित करने वाली समस्या क्या शीर्ष स्तर पर एक अच्छी पहल करने से हल हो जाएगी? या फिर उसका सफाया करने के लिए उतने ही व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने की जरूरत है? ऐसा अभियान जिसमें आम आदमी स्वत: शामिल हो? पांच दिन के आंदोलन ने आम आदमी की उम्मीदें और अपेक्षाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दी हैं। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में मैंने हरियाणा के कुछ ग्रामीणों की चर्चा सुनी। एक व्यक्ति का कहना था कि अन्ना हजारे को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। किसी का जवाब था कि यह पद उनके लिए बहुत छोटा है, को और बड़ा पद मिलना चाहिए। एक अन्य यात्री ने कहा कि मैं अन्ना का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता था कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को वाजिब सम्मान और उनके परिवारों को जरूरी सहायता क्यों नहीं मिलती? किसी ने कहा कि मैं उनसे जरूर मिलकर यह पूछूंगा कि आतंकवाद और हत्याओं में लिप्त अपराधियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती। एक यात्री ने निराशा जताते हुए कहा कि मैं तो अन्ना के साथ चल पड़ूं लेकिन मजबूरी है कि मेरे छोटे-छोटे बच्चें हैं। अन्ना के लिए बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पास इन सबके जवाब होने चाहिए। इन सवालों और चर्चाओं की व्यावहारिकता में मत जाइए। मुद्दा यह है कि लोग अन्ना को सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन क्या अन्ना के पास इन सब मुद्दों, सवालों, समस्याओं और चुनौतियों के जवाब हो सकते हैं?

लोकपाल तो एक प्रतीक है

रालेगण सिद्धी का एक बुजुर्ग गांधीवादी भारत के 'एंग्री यंग मैन' की आशाओं का केंद्र बन गया। जिस तरह बच्चें, युवक, बुजुर्ग, स्त्रियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अपनी-अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और भाषायी प्रतिबद्धताओं को भूलकर उनके साथ खड़े हुए वह अद्वितीय था। जन अपेक्षाओं का वह एक अजीब, रोमांचक उफान था जो केंद्र सरकार की राजनैतिक चतुराई की वजह से पांच दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। भले ही आप इसे चुनावी विवशता मानें या चौतरफा हमलों से घिरी सरकार की राजनैतिक मजबूरी, केंद्र के सामने इसे स्वीकार करने के अलावा को चारा ही नहीं था। कुछ और दिन बीतते तो जनभावनाओं का वह बढ़ता ज्वार सुनामी में तब्दील हो जाता। एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता में यही फर्क होता है। नेता समय की नजाकत को अच्छी तरह पढ़ना जानता है। संप्रग सरकार ने न सिर्फ अन्ना हजारे की सभी मांगें मानने का फैसला किया बल्कि उन्हें माना भी तुरत-फुरत। असंतुष्ट मध्य वर्ग, उग्र युवा, बाग-बाग मीडिया और ऊपर से इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में आकार लेती हुई वर्चुअल रिवोल्यूशन। इससे पहले कि हालात मिस्र की तर्ज में बदलते, सरकार का फैसला आ गया। रातोंरात अधिसूचना जारी कर दी गई। राजपत्र का प्रकाशन भी हो गया। अनशन समाप्त हो गया और उसके साथ ही दब गया वह बवंडर जो हालात को विध्वंसक मोड़ दे सकता था। इसे आप सरकार की जीत कहेंगे या हार?

अन्ना हजारे का आंदोलन जन लोकपाल विधेयक को लेकर था। परोक्ष रूप से यह विधेयक भ्रष्टाचार के खात्मे का प्रतीक बन गया। सरकार ने उनकी मांगें मान लीं। विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति में आधे लोग सिविल सोसायटी से होंगे, इसमें अब को संदेह नहीं बचा। उसका नेतृत्व भी दो लोग करेंगे जिनमें से एक सरकारी और एक गैर-सरकारी होंगे। मान कर चलना चाहिए कि मसौदा समय पर तैयार हो जाएगा और विधेयक संसद में पास हो जाएगा। अंत में जन लोकपाल की स्थापना भी हो जाएगी। उसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और अफसरशाहों से लेकर जन प्रतिनिधि तक आ जाएंगे। किंतु क्या अनेक संस्थाओं की तर्ज पर एक और संस्था की स्थापना भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी है? देश के हर दूसरे नागरिक को प्रभावित करने वाली समस्या क्या शीर्ष स्तर पर एक अच्छी पहल करने से हल हो जाएगी? या फिर उसका सफाया करने के लिए उतने ही व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने की जरूरत है? ऐसा अभियान जिसमें आम आदमी स्वत: शामिल हो? सिर्फ बिल का मसौदा बनवाने और उसे पास करवाने में ही इतिश्री मान लेना काफी नहीं होगा। ऐसी संस्थाओं को किस तरह 'हैंडल' किया जाता है, यह राजनेता अच्छी तरह जानते हैं। और फिर 'सिस्टम' का हिस्सा बनने के बाद विद्रोही से विद्रोही व्यक्ति भी किस तरह 'व्यवस्थागत अनुशासन' में निबद्ध हो जाता है, इसके उदाहरणों की कमी नहीं है। जन लोकपाल बिल को लक्ष्य मानने की बजाए एक बहुत लंबी प्रक्रिया की शुरूआत मानिए। ऐसी प्रक्रिया जो न तो सरकार से शुरूहोती है और न सरकार पर खत्म। स्थायी जन भागीदारी के बिना भ्रष्टाचार के उन्मूलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती।

सर्वव्यापी सत्य

भ्रष्टाचार की समस्या का आकार तो देखिए। वह अमावस के अंधकार की तरह एक सर्वव्यापी सत्य है। केंद्र से लेकर राज्य तक, राजधानियों से लेकर जिलों तक, तहसीलों से लेकर गांव-गांव तक, सरकारों से लेकर प्रशासन तक, अफसर से लेकर चपरासी तक, वह हमारे समाज की धमनियों में बहुत गहरा तक पहुंची हुई है। वह एक सर्वव्यापी कैंसर है। वह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बनी हुई है, बल्कि समाज, प्रशासन और राजनीति में एक किस्म की 'व्यवस्था' सुनिश्चित करने की स्थिति में है। भ्रष्टाचार रक्षा सौदों और दूरसंचार लाइसेंसों तक सीमित नहीं है। वह तो गांव-गांव में बसता है। मनरेगा, सरकारी भर्तियां, निचले स्तर के ठेके, निचली अदालतें, पंचायतें, पटवारी, राशन प्रणाली, किसानों के कर्जों, पुलिस की शिकायतों तक में फैला हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट काक ने कार्टून बनाया था कि तुम भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हो, एक यही तो है जिसकी बदौलत यह देश चल रहा है! क्या जन लोकपाल या ऐसा ही को अन्य विधेयक या केंद्रीय संस्थान उतने ही महाव्यापक प्रभाव वाली दवा है, जितने सर्वव्यापी किस्म की यह बीमारी है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और बड़े आंदोलन की योजना बनाइए। यह आंदोलन किसी सरकार, संस्थान या नेता के विरुद्ध केंद्रित नहीं होगा बल्कि समाज की मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला आंदोलन होगा।

आंदोलन का पहला चरण सफल रहा। इस बात को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि यह सार्थक और परिणामोन्मुख भी सिद्ध हो। जन लोकपाल नामक संस्था हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद किस तरह काम करेगी, उस पर गंभीर मंथन और एहतियाती प्रावधान करने की जरूरत है। अन्यथा तथाकथित निवारक संस्थाओं की हमारे यहां कमी नहीं है। पुलिस की मौजूदगी अपराधों को खत्म नहीं कर पाई, न्यायपालिका के होने से विवाद दूर नहीं हुए और सतर्कता आयुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की उपस्थिति भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकी, सीएजी की मौजूदगी से आर्थिक अनियमितताएं बंद नहीं हुई और बैंकिंग लोकपाल की मौजूदगी से बैंकिंग व्यवस्था लुटिहीन नहीं बन पाई। अन्ना और दूसरे लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि जन लोकपाल के मामले में ऐसा न हो।